

# Bihar Administrative Service Association

**Shashank Shekhar Sinha**  
**President**

Mob. No.- 9334118192



**Sunil Kumar Tiwary**  
**General Secretary**

Mob. No.- 9431085120

Memo No. .... 29 .....

Date ..... 13/06/23

**Vice President**

Ajay Kumar



9835737317

**Subodh Kumar**



7979919465

**Joint Secretary**

Chandrashekhar Azad



8987044905

**Vikash Kumar**



7717770977

**Treasurer**

Shashi Shekhar



9334557086

सेवा में,

माननीय मंत्री वित्त विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

विषय:- भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no.-57/05/2021-P&PW (B), Dated- 03.03.2023 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 31.08.2005 के द्वारा यह आदेश निर्गत हुआ कि दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को नई पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित किया जायेगा (अनुलग्नक I संलग्न)। इसी क्रम में दिनांक-01.09.2005 के बाद नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी नई पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित किया गया है। हाल में नई पेंशन योजना के संबंध में भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no 57/05/2021-P&PW(B), Dated 03.03.2023 के द्वारा एक अधिसूचना निर्गत किया गया है कि जैसे सरकारी कर्मी जिनकी नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22.12.2003 या उसके पूर्व निर्गत हो, लेकिन उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार के अधीन 01.01.2004 से लागू नई पेंशन योजना (NPS) के बाद हुई हो, उनको भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से लाभान्वित करने हेतु दिशा निदेश जारी किये गये हैं, जिसके कंडिका 4 में उल्लिखित प्रावधान निम्नवत है :-

**The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs**

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna- 800001

Website : [basabihar.org](http://basabihar.org), E-mail Id: [basassociationbihar@gmail.com](mailto:basassociationbihar@gmail.com)

**in the light of the various representations / references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided then, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/ notified for recruitment/appointment, prior to the date of notification for National Pension System i.e 22.12.2003 and is covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be covered under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants latest by 31.08.2023.**

(अनुलग्नक II संलग्न )

अतः भारत सरकार से निर्गत उक्त पत्र के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से लाभान्वित करने के निम्नलिखित आधार हैं :-

1. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों हेतु चिन्हित रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 03.02.2004 (दैनिक जागरण) (अनुलग्नक III संलग्न ) एवं दिनांक-05.11.2004 (Times of India) (अनुलग्नक IV संलग्न) को किया गया था ।

2. इस क्रम में दिनांक 03.02.2004 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में 46वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका-6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक-31.03.2004 के पूर्व की तथा दिनांक-14.12.2004 को हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण सहित अन्य समाचार पत्रों में 47वीं संयुक्त (प्रा0) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका-6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक-01.08.2001 के पहले की होनी चाहिए जिसे बाद में 31.12.2004 तक औपबधिक रूप से कट-ऑफ डेट निर्धारित किया गया ।

3. उक्त विज्ञापनों के आधार पर दिनांक-18 जून, 2007 को 46वीं बैच के चयनित पदाधिकारियों की अधिसूचना बिहार गजट (अनुलग्नक- V संलग्न) में प्रकाशित की गई तथा 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक-24.01.2009 (अनुलग्नक- VI संलग्न) को प्रकाशित किया गया ।

4. उपर अंकित संलग्न अनुलग्नक-III, 46वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका-1 में अधिकतम उम्र सीमा दिनांक-01.08.2000 तथा अनुलग्नक- IV संलग्न, 47 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका-1 में अधिकतम उम्र की गणना दिनांक-01.08.2001 के आधार पर किया जाना स्पष्ट किया गया है ।

5. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि 46वीं एवं 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन, चयन की अधिसूचना तक कहीं भी नई पेंशन योजना से उक्त रिक्तियों को आच्छादित किया जाना स्पष्ट नहीं किया गया है अर्थात उक्त दोनों 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के


पदाधिकारीगण दिनांक-01.09.2005 के पहले के प्रचलित पेंशन नियमावली के आलोक में ही विज्ञापन प्रकाशित की गयी है ।

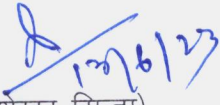
6. इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा अपने पत्र संख्या-21, दिनांक-13.07.2021 द्वारा भी प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को C.W.J.C. संख्या-10901/2006 मो0 क्यूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार (अनुलग्नक-VII संलग्न) वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-03.08.2011 को पारित आदेश- **It is in fact this aspect of matter which would clinch the issue in favour of the petitioners in as much as it is well settles by now that old vacancies have to be Government by the old rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules cannot be made applicable** के आलोक में- "नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किए गए पदाधिकारियों / कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय ", अनुरोध किया गया था (अनुलग्नक- VIII संलग्न) ।

7. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि C.W.J.C. संख्या-2312/2022 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ बनाम बिहार सरकार वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया है जो प्रक्रियाधीन है (अनुलग्नक- IX संलग्न ) भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त पत्र में भी विभिन्न विभागों से विमर्शोपरान्त तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में उक्त निर्णय लिया जाना उल्लिखित है ।

बिहार सरकार द्वारा भी उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में सकारात्मक निर्णय लिया जाता है एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किया गया है तो उभय पक्षों का माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद में समय एवं संसाधन के अपव्यय से बचा जा सकेगा ।

अतः अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. संख्या-10901/2006 मो0 क्यूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार में दिनांक-03.08.2021 को पारित आदेश एवं भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no.-57/05/2021-P&PW (B), Dated-03.03.2023 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधानों के अधीन पुरानी पेंशन योजना(OPS) का लाभ दिए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे ।  
अनुलग्नक :- यथोपरि ।

  
(सुनील कुमार तिवारी)  
महासचिव,  
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ,  
बिहार, पटना ।

विश्वासभाजन  
  
(शशांक शंखर सिन्हा)  
अध्यक्ष,  
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ,  
बिहार, पटना ।

परिच्छिष्ट - I

87-

सचिका संख्या- वि०(27)प०को०-53/04 - 1964

बिहार सरकार  
वित्त विभाग

पटना, दिनांक- 31.8.2005

संकल्प

विषय:- दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन योजना ।

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर, लिये गये निर्णयों के आलोक में सम्प्रति राज्यकर्मियों को केन्द्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप वेतनमान, भत्ता, सेवानिवृत्ति की आयु आदि की सुविधायें अनुमान्य है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय प्रभाग, नई दिल्ली के पत्रांक-05/07/2003 ई०सी०वी० दिनांक-22.12.2003 द्वारा भारत सरकार के अधीन दिनांक-01.01.2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए वर्तमान में प्रचलित पेंशन योजना के स्थान पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है । परन्तु भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए प्रख्यापित अंशदायी पेंशन योजना के सदृश्य राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत दिनांक-01.09.2005 के प्रभाव से अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम "बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना-2005" होगा ।

3. इस संकल्प में निहित प्रावधान जैसे सरकारी सेवकों के मामले में लागू हेमिजिन्की नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन दिनांक-01.09.2005 को या उसके बाद हुई हो, परन्तु उक्त प्रावधान संविदा, लोक उपक्रमों एवं स्वायत्त संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर आय कर्मियों, दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों तथा पुनर्नियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होगा ।

4. दिनांक-01.09.2005 या उसके बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कर्मियों के गारिफ वेतन आदि से मूल वेतन+अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग की 10 (दस) प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में कटौती की जायेगी तथा उतनी ही राशि नियोक्ता अर्थात् राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी ।

5. योजनान्तर्गत संबंधित कर्मियों के अंशदान की कटौती उनके योगदान के अगले माह से प्रारम्भ होगी, अर्थात् यदि सितम्बर, 2005 में किसी ने योगदान किया हो तो अंशदान की कटौती अक्टूबर, 2005 के माह से प्रारम्भ होगी ।

6. योजना प्रवृत्त होने की तिथि 01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामलों में वर्तमान में लागू सामान्य भविष्य निधि तथा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात् सामान्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की कटौती नहीं की जायेगी ।

7. योजनान्तर्गत अंशदान की कटौती तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये अंशदान संबंधी लेखा का प्रथम तत्काल भविष्यनिधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा किया जायेगा तथा भविष्य निधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना के अधीन अंशदान की कटौती के लिए एक लेखा संख्या आवंटित की जायेगी ।

8. नई पेंशन योजनान्तर्गत संबंधित कर्मों की सेवानिवृत्ति के समय सेवाकाल में संचित निधि की 60(चासीस) प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से वार्षिकी खरीदने (आई० आर० डी० ए० नियंत्रित जीवन बीमा कम्पनी से) के लिए कटौती कर ली जायेगी जिससे सरकारी कर्मचारी तथा उस पर आश्रित उसके माता-पिता तथा पति-पत्नी के जीवन काल हेतु पेंशन की व्यवस्था की जायेगी तथा शेष 60(साठ) प्रतिशत राशि एक

10/10/05

सूक्त

सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को भुगतान कर दी जायेगी ।

9. इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अलग से विस्तृत आदेश निर्गत किये जा रहे हैं ।

10. जब तक पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण गठित नहीं हो जाता है, तबतक कर्मियों तथा अंशदान की राशि लोक लेखा में रखी जायेगी तथा इस पर सामान्य भविष्य निधि की दर से व्याज देय होगा ।

11. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय आदि जहाँ राज्य सरकार के कर्मियों की भांति पेंशन की सुविधा उपलब्ध है को इस नई अंशदायी पेंशन योजना को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाये

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ज्ञापक- 1964 (27) 53/04-1964 पटना, दिनांक- 31. 8. 2005  
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पी० एन० नारायणन,  
वित्त आयुक्त । 31/8/5

ज्ञापक- 1964 (27) 53/04-1964 पटना, दिनांक- 31. 8. 2005  
प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/निबंधक उच्च न्यायालय पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सभी समाह्वता/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समावेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पी० एन० नारायणन,  
वित्त आयुक्त । 31/8/5

ज्ञापक- 1964 (27) 53/04-1964 पटना, दिनांक- 31. 8. 2005  
प्रतिलिपि- संयुक्त आयुक्त लेखा प्रशासन, पंत भवन, पटना/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

भगत चौधरी,  
उप सचिव । 31/8/5

ज्ञापक- 1964 (27) 53/04-1964 पटना, दिनांक- 31. 8. 2005  
प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

भगत चौधरी,  
उप सचिव । 31/8/5

अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 1000 प्रति मुद्रित कर वित्त विभाग (पेंशन कोषांग) को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए ।

भगत चौधरी,  
उप सचिव । 31/8/5

No. 57/05/2021-P&PW(B)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,

New Delhi, the 03<sup>rd</sup> March, 2023

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, in place of National Pension System, of those Central Government employees who were recruited against the posts/vacancies advertised /notified for recruitment, on or before 22.12.2003.**

The undersigned is directed to say that consequent on introduction of National Pension System (NPS) vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003, all Government servants appointed on or after 01.01.2004 to the posts in the Central Government service (except armed forces) are mandatorily covered under the said scheme. The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and other connected rules were also amended vide Notification dated 30.12.2003 and, after the said amendment, those rules are not applicable to the Government servants appointed to Government service after 31.12.2003.

2. Subsequently, Department of Pension and Pensioners' Welfare in consultation with the Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of Hon'ble Courts, issued instructions vide OM No. 57/04/2019-P&PW(B) dated 17.02.2020 giving one time option to Central Government employees who were declared successful for recruitment in the results declared on or before 31.12.2003 against vacancies which occurred before 01.01.2004 and were covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 ( now 2021). There was fixed time schedule for different activities under the aforesaid OM dated 17.02.2020.

3. Representations have been received in this Department from the Government servants appointed on or after 01.01.2004 requesting for extending the benefit of the pension scheme under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021) on the ground that their appointment was made against the posts/vacancies advertised/notified for recruitment prior to notification for National Pension System, referring to court judgments of various Hon'ble High Courts and Hon'ble Central Administrative Tribunals allowing such benefits to applicants.

4. The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided that, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, prior to the date of notification for National Pension System i.e. 22.12.2003 and is covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants latest by 31.08.2023.

5. Those Government servants who are eligible to exercise option in accordance with para-4 above, but who do not exercise this option by the stipulated date, shall continue to be covered by the National Pension System.

6. The option once exercised shall be final.

7. The matter regarding coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), based on the option exercised by the Government servant, shall be placed before the Appointing Authority of the posts for which such option is being exercised for consideration, in accordance with these instructions. In case the Government servant fulfills the conditions for coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), in accordance with these instructions, necessary order in this regard shall be issued latest by 31<sup>st</sup> October, 2023. The NPS account of such Government servants shall, consequently, be closed w.e.f. 31<sup>st</sup> December, 2023.

8. The Government servants who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), shall be required to subscribe to the General Provident Fund (GPF). Regarding account of the corpus in the NPS account of the Government servant, Controller General of Accounts (CGA) has furnished the following clarification vide letter No. 1(7)(2)/2010/cla./TA III/390 dated 14.11.2019 & I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022:

- i. **Adjustment of Employees' contribution in Accounts:** Amount may be credited to individual's GPF account and the account may be recasted permitting up-to-date interest (Authority-FR-16 & Rule 11 of GPF Rules).
- ii. **Adjustment of Government contribution under NPS in Accounts:** To be accounted for as (-) Dr. to object head 70 - Deduct Recoveries under Major Head 2071 - Pension and other Retirement benefit - Minor Head 911- Deduct Recoveries of over payment (GAR 35 and para 3.10 of List of Major and Minor Heads of Accounts).



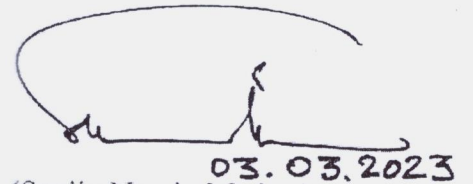
- iii. **Adjustment of increased value of subscription on account of appreciation of investments** – May be accounted for by crediting the amount to Govt. account under M.H. 0071- Contribution towards Pension and Other Retirements Benefits 800- Other Receipts (Note under the above Head in LMMHA).

9. All Ministries/Departments are requested to give wide publicity to these orders without fail. The cases of those Government servants who fulfill the conditions mentioned in this O.M. and who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) may be settled by the administrative Ministries/Departments in accordance with these orders.

10. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No. 1(7)/EV/2019 dated 05.12.2022 & 07.02.2023 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022.

11. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

12. Hindi version will follow.



03.03.2023

(Sanjiv Narain Mathur)

Additional Secretary to Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. Ministry of Railways, Railway Board, for information, New Delhi.
5. Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.
6. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
7. AD (OL) for Hindi version.
8. NIC for uploading on Department's website.





बिहार लोक सेवा आयोग

15 नवम्बर 2004 नवम्बर मास (बंगला गेट) पटना - 800001

47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा

27

विद्यमान नियमों के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है... 1. उम्मीदवार का नाम (पूरा नाम) ... 2. पिता का नाम ... 3. जन्म तिथि ... 4. पता ... 5. शिक्षा ... 6. अनुभव ... 7. फोटो ... 8. हस्ताक्षर ... 9. मुद्रांक ... 10. प्रवेश शुल्क ... 11. परीक्षा शुल्क ... 12. परीक्षा केंद्र ... 13. परीक्षा तिथि ... 14. परीक्षा का विषय ... 15. परीक्षा का स्तर ... 16. परीक्षा का स्तर ... 17. परीक्षा का स्तर ... 18. परीक्षा का स्तर ... 19. परीक्षा का स्तर ... 20. परीक्षा का स्तर ... 21. परीक्षा का स्तर ... 22. परीक्षा का स्तर ... 23. परीक्षा का स्तर ... 24. परीक्षा का स्तर ... 25. परीक्षा का स्तर ... 26. परीक्षा का स्तर ... 27. परीक्षा का स्तर ... 28. परीक्षा का स्तर ... 29. परीक्षा का स्तर ... 30. परीक्षा का स्तर ... 31. परीक्षा का स्तर ... 32. परीक्षा का स्तर ... 33. परीक्षा का स्तर ... 34. परीक्षा का स्तर ... 35. परीक्षा का स्तर ... 36. परीक्षा का स्तर ... 37. परीक्षा का स्तर ... 38. परीक्षा का स्तर ... 39. परीक्षा का स्तर ... 40. परीक्षा का स्तर ... 41. परीक्षा का स्तर ... 42. परीक्षा का स्तर ... 43. परीक्षा का स्तर ... 44. परीक्षा का स्तर ... 45. परीक्षा का स्तर ... 46. परीक्षा का स्तर ... 47. परीक्षा का स्तर ...

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदनपत्र - (अनुसूचक वर्ग के उम्मीदवारों के लिए) प्रारंभिक - 'क'

आवेदनपत्र की प्रतिलिपि (दोस्ताने) ... 1. उम्मीदवार का नाम (पूरा नाम) ... 2. पिता का नाम ... 3. जन्म तिथि ... 4. पता ... 5. शिक्षा ... 6. अनुभव ... 7. फोटो ... 8. हस्ताक्षर ... 9. मुद्रांक ... 10. प्रवेश शुल्क ... 11. परीक्षा शुल्क ... 12. परीक्षा केंद्र ... 13. परीक्षा तिथि ... 14. परीक्षा का विषय ... 15. परीक्षा का स्तर ... 16. परीक्षा का स्तर ... 17. परीक्षा का स्तर ... 18. परीक्षा का स्तर ... 19. परीक्षा का स्तर ... 20. परीक्षा का स्तर ... 21. परीक्षा का स्तर ... 22. परीक्षा का स्तर ... 23. परीक्षा का स्तर ... 24. परीक्षा का स्तर ... 25. परीक्षा का स्तर ... 26. परीक्षा का स्तर ... 27. परीक्षा का स्तर ... 28. परीक्षा का स्तर ... 29. परीक्षा का स्तर ... 30. परीक्षा का स्तर ... 31. परीक्षा का स्तर ... 32. परीक्षा का स्तर ... 33. परीक्षा का स्तर ... 34. परीक्षा का स्तर ... 35. परीक्षा का स्तर ... 36. परीक्षा का स्तर ... 37. परीक्षा का स्तर ... 38. परीक्षा का स्तर ... 39. परीक्षा का स्तर ... 40. परीक्षा का स्तर ... 41. परीक्षा का स्तर ... 42. परीक्षा का स्तर ... 43. परीक्षा का स्तर ... 44. परीक्षा का स्तर ... 45. परीक्षा का स्तर ... 46. परीक्षा का स्तर ... 47. परीक्षा का स्तर ...

Times of India - 05-11-2004

Certified Section Officer Bihar Public Service Commission PATNA

विधान सं. पी० टी०-4०



# बिहार राजपत्र

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं० पृष्ठ 578)

6 अक्टूबर 1929 (सं०)

पृष्ठ सं० 37 जून 2007

कार्यपालक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

18 जून 2007

सं०-12/नं०-1002/2007का०-6260-बिहार लोक सेवा आयोग की 86वीं संपुन्न प्रविणामिका नमोदा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए निम्नलिखित 43 (चत्वारिंश) अनुसूचित संप्रदायों को सार्वजनिक सेवा के अधीन वर्तमान 6500-10,500/- में सरकार द्वारा समय-समय पर स्थायी अनुक्रम पत्रों के साथ औपचारिक रूप में परीक्षण उप-संलग्नकों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. संशोधित परीक्षण उप-संलग्नकों को उनके काम के समान अंकित विषयों में व्यवहारिक प्रकाशन हेतु परस्परपिबन्धित किया जाता है -

क्रम सं०	नाम	संपुन्न सं० क्रमिक	आरक्षण विधिति	व्यवहारिक प्रकाशन हेतु अंकित विज्ञापन सं०
1	2	3	4	5
1	श्री गो० रामचंद्र	1	सामान्य	पटना
2	श्री गो० जगत आराम	7	सामान्य	बंका
3	श्री अरुण कुमार सिंह	12	सामान्य	मधुवा
4	श्री सुन्दर कुमार	13	सामान्य	छादिवा
5	श्री रामा राधा प्रसाद	14	सामान्य	सहारन
6	श्री राम राम राम	16	सामान्य	मैथिल (अनुसूचित)
7	श्री राजेश सिंह	17	सामान्य	मुंगेर
8	श्री आनंद कुमार	18	सामान्य	फरिक्ता
9	श्री रामा अरुण	19	सामान्य	समस्तीपुर
10	श्री सुरेश कुमार	20	सामान्य	सुपौल (अनुसूचित)
11	श्री विष्णु अरुण	21	सामान्य	समस्तीपुर
12	श्री राम प्रकाश राम	22	सामान्य	सुपौल
13	श्री प्रकाश राम	24	सामान्य	जलालपुर
14	श्री गो० राम	25	सामान्य	बेहनाबाद

14

बिहार गजट (असाधारण), 27 जून 2007

क्र.सं. (1)	नाम (2)	संयुक्त सेवा क्रमिक (3)	आवश्यक स्थिति (4)	स्थायित्व प्रमाण हेतु आवंटित जिला (5)
15	श्रीमती किष्कि मिश्र	26	सामान्य	औरंगाबाद
16	श्री पुष्परा कुमारी	27	सामान्य	सारन (रुपरा)
17	श्री सुधीर कुमार	29	सामान्य	लाखीसराय
18	श्री परमानन्द झा	30	सामान्य	मध्या
19	श्री मोहन आर्याक जैन	31	सामान्य	गोपालगंज
20	श्री प्रभात चन्द्र	32	सामान्य	सौवान
21	श्री विवेक	35	पिछड़ी जाति	शेखरपुर
22	श्री शिव राजेंद्र ठाकुर	36	अत्यन्त पिछड़ी जाति	परिव्रज चम्पारण
23	श्री अमरेंद्र कुमार	40	पिछड़ी जाति	मुजफ्फरपुर
24	श्री मोहन नरेश शर्मा	43	अत्यन्त पिछड़ी जाति	सोनीमढी
25	श्री प्रमोद कुमार खन्ना	45	पिछड़ी जाति	शिवहर
26	श्री विनोद कुमार	46	पिछड़ी जाति	पूर्वी चम्पारण
27	श्री मोहन रामेश्वर शर्मा	47	अत्यन्त पिछड़ी जाति	वैशाली
28	श्री प्रमोद कुमार	49	अत्यन्त पिछड़ी जाति	दरभंगा
29	श्री प्रभात कुमार	51	पिछड़ी जाति	पटना
30	श्री प्रभात कुमार	53	अत्यन्त पिछड़ी जाति	मधुबनी
31	सुधीर शर्मा	56	पिछड़ी जाति महिला	सहस्ना
32	श्री शाहनवाज अहमद निशाजी	57	अत्यन्त पिछड़ी जाति	समस्तीपुर
33	श्री मोहन सुनील शर्मा	61	अत्यन्त पिछड़ी जाति	जमुई
34	श्री नरेश ठाकुर शर्मा	62	अत्यन्त पिछड़ी जाति	बेगूसराय
35	श्री प्रवेश कुमार	63	अत्यन्त पिछड़ी जाति	सुपौल
36	श्री प्रवेश कुमार	70	अनुसूचित जाति	मधुबनी
37	श्री विद्यानाथ रामखन	137	अनुसूचित जाति	नर्मिया
38	श्री राजेश्वर	169	अनुसूचित जाति	अपरक
39	श्री राजेश कुमार	187	अनुसूचित जाति	किसानगंज
40	श्री मनोज कुमार	197	अनुसूचित जाति	कटिहार
41	सुधीर प्रमोद शर्मा अर्चना	199	अनुसूचित जाति	मुजफ्फरपुर
42	श्री सुधीर कुमार	206	अनुसूचित जाति	भागलपुर

उपरोक्त औपचारिक नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है:-  
 (क) रियासत/अवकाश पूर्व की प्रतिष्ठित एवं पूर्ववर्त सत्यापन संबंधी कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से निरस्त की जाए सकती है।  
 (ख) सम्पत्ति प्रमाण पत्रों/सम्पत्ति सौद/अन्य प्रमाण पत्रों को सत्यापित में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से रुकती है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।  
 (ग) औपचारिक रूप से नियुक्त कर्मियों पर नियमानुसार वेतन-समानता अपने नाम को सम्बन्धित लिखित लिखित पत्र द्वारा प्रमाण पत्र के अन्तर्गत् प्रमाण पत्रों एवं प्रमाण पत्र के एक प्रति कार्यालय एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजें।  
 (घ) निम्नलिखित कर्मियों को नियुक्ति पत्र तक स्वीकृत नहीं हो सकेगा, यदि उनके द्वारा मूल स्नातक डिग्री/संशुद्ध प्रमाणपत्रों द्वारा निर्गत मान्य सत्य प्रमाणपत्र/आवधिक प्रमाण-पत्र, जिसे पूर्व में विभाग को सम्पत्ति नहीं किया गया हो, प्रमाण पत्रों में सम्पत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमाणपत्रों का यह शक्ति होगा कि मूल प्रमाण-पत्र रद्द कर सत्यापित प्रमाणपत्रों के अन्तर्गत प्रमाणपत्रों को अधिसूचित किया प्रति शेष हेतु विभाग को उनके सम्पत्ति प्रमाणपत्रों का एक प्रति भेजें।  
 (ङ) प्रमाणपत्रों को अपने अधिसूचित प्रमाणपत्र निष्पत्ति पत्र समलया करके भेजा जा रहा है।  
 (च) आवधिक प्रमाणपत्रों की प्रमाणपत्र निष्पत्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर कोई प्रमाणपत्र स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

बिहार-उपखण्ड के अन्तर्गत  
 और सुपुत्री  
 राज्य के सचिव

आचार्य शिव प्रसाद शर्मा एवं प्रकाश, पटना हाउस प्रकाशित  
 राजेश्वर, सचिवालय महालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।  
 (विभागीय असाधारण) 571-5714-200-210 210 210-210



**बिहार लोक सेवा आयोग**  
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बैली रोड), पटना - 800001  
47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का एल

47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंतर्गत साक्षात्कार हेतु व्ययित कुल 224 उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार दिनांक 12.01.2009 से 14.01.2009 की अवधि में सम्पन्न हुआ। उक्त मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार में चार उम्मीदवार, अनुक्रमांक 129046, शम्भु कुमार, अनुक्रमांक 129580, हरिचंद्र नाथ, अनुक्रमांक 138612, संजय कुमार एवं अनुक्रमांक 149923, संजय नारती ने भाग नहीं लिया। शेष उक्त उम्मीदवारों को उनकी (मुख्य) लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तियों की जोड़ के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त क्रमिक मेधा सूची के अधीन, राज्य स्तर/सेवाओं के लिए उनके द्वारा इंगित अधिमान-क्रम को प्रथम देते हुए, व्ययित सेवा के लिए उनकी सुयोग्यता तथा आकांक्षित पद-उपलब्धता के अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को इंगित राज्य स्तर/सेवा में नियुक्ति हेतु सफल घोषित किया जाता है-

क्रम सं.	अनुक्रमांक	नाम	मेधा क्रमांक	आर्बेट आकांक्षित रीस्टर स्थिति
<b>(1) बिहार प्रशासनिक सेवा:</b>				
1.	134300	हरिचंद्र प्रसाद कुशवाहा	5	सामान्य
2.	107027	राजेश्वरी पाण्डेय	6	सामान्य
3.	110993	कुमार प्रशान्त	7	सामान्य
4.	124075	नीरज कुमार दास	8	सामान्य
5.	142539	शम्भु नाथ	9	सामान्य
6.	103574	किशोर कुमार	10	सामान्य
7.	128331	संजीव कुमार	11	सामान्य
8.	119188	दुर्गा कुमार	12	सामान्य
9.	902912	चन्द्रशेखर आजाद	13	सामान्य
10.	119308	राजेश कुमार	14	सामान्य
11.	163082	गिरिजा कुमार	15	सामान्य
12.	150049	अमित कुमार तिवारी	16	सामान्य
13.	167769	देवेन्द्र प्रताप शाही	17	सामान्य
14.	147379	शशि शंकर	18	सामान्य
15.	102328	शुभु कान्त	20	सामान्य
16.	108254	शैलेश चन्द्र दिवाकर	21	सामान्य
17.	164993	नीतू सिंह	22	सामान्य
18.	151985	सामानुज प्रसाद सिंह	23	सामान्य
19.	103584	अश्विनी कुमार	26	पिछड़ा वर्ग
20.	106904	अमित कुमार गुप्ता	26	पिछड़ा वर्ग
21.	130314	चुरेण कुमार अलबेला	29	पिछड़ा वर्ग
22.	162363	संजय कुमार सिंह	33	पिछड़ा वर्ग
23.	158938	अशोक कुमार गुप्ता	35	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
24.	106134	अनु कुमार	43	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
25.	130441	प्रतिभ सिंह	48	पिछड़ा वर्ग को महिला
26.	113825	बुद्ध प्रसाद	52	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
27.	116220	कपूर अंतारी	64	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
28.	132587	साम कुमार	85	पिछड़ा वर्ग (विकलांग)
29.	120076	अजितकुमार अंतारी	78	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
30.	140103	सुकेत कुमार	78	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
31.	138304	देवेंद्र राम	104	अनुसूचित जाति
32.	112104	कुमार बलराम	128	अनुसूचित जाति
33.	127912	अरुण प्रकाश	163	अनुसूचित जाति
34.	125491	विशाल आनन्द	185	अनुसूचित जाति
35.	135005	सैफ भूषण किशोर	168	अनुसूचित जाति
36.	156491	गौरी कुमार	171	अनुसूचित जाति
<b>(2) बिहार आरक्षी सेवा:</b>				
37.	112655	राजेश कुमार	1	सामान्य
38.	113777	अरुण कुमार झा	2	सामान्य
39.	155171	राजेश कुमार सिंह प्रभाकर	3	सामान्य
40.	146255	रम्य रंजन हरगोटे	4	सामान्य
41.	120385	संजीव कुमार	56	अनुसूचित जाति
<b>(3) अधिव्यक्ति अधिकारी:</b>				
42.	108275	नरेश प्रताप सिंह	24	सामान्य
43.	171878	सुकेत कुमार	25	सामान्य
44.	122821	शशिकांत चतुर्वेदी	27	सामान्य
45.	158434	सैफ रंजन आलोक	50	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
46.	143830	संजय कुमार	185	अनुसूचित जाति

क्रम सं.	अनुक्रमांक	नाम	मेधा क्रमांक	आर्बेट आकांक्षित रीस्टर स्थिति
<b>(4) अवर पिछड़ा वर्ग:</b>				
47.	102259	राजेश कुमार सिंह	30	सामान्य
48.	121836	रवि कुमार सिंह	32	सामान्य
49.	100061	प्रमोद कुमार	39	पिछड़ा वर्ग
50.	164957	संजय कुमार	44	पिछड़ा वर्ग
51.	105170	मनीष कुमार	80	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
52.	112074	मोहन कुमार	172	अनुसूचित जाति
<b>(5) बिना अकेला पदाधिकारी:</b>				
53.	101014	सुभाष चंद्र वर्मा	31	सामान्य
54.	130083	प्रदीप कुमार सिंह	34	सामान्य
55.	112420	राजेश कुमार	36	सामान्य
56.	111120	सुदीप शर्मा	45	सामान्य
57.	119492	संजय कुमार	47	सामान्य
58.	135891	विजयशंकर राजेश	193	अनुसूचित जाति
59.	156714	बनारस चंद्रिका	194	अनुसूचित जाति
<b>(6) कनिष्ठ अधिकारी:</b>				
60.	127127	संजय शर्मा	37	सामान्य
61.	140208	विजय कुमार अरोड़ा	41	सामान्य
62.	100888	जयशंकर लाल प्रभाकर	46	सामान्य
63.	108571	राजेश कुमार झा	49	सामान्य
64.	123289	विद्या भूषण मिश्रा	51	सामान्य
65.	148624	मनीष कुमार	53	सामान्य
66.	149150	संजय कुमार शर्मा	54	पिछड़ा वर्ग
67.	164123	राजेश कुमार	91	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
68.	163416	सतीश लाल	116	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
69.	164997	जयशंकर शर्मा	190	अनुसूचित जाति
70.	105892	अनिल पासवान	195	अनुसूचित जाति
<b>(7) सहायक निबंधक, सहयोगी सचिवियाँ:</b>				
71.	120733	संजीव कुमार सिंह	38	सामान्य
72.	171217	सैफ रंजन	42	सामान्य
73.	129699	संजय प्रसाद	60	पिछड़ा वर्ग
74.	103206	श्री. इन्द्रजित आलम	88	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
75.	127584	राज कुमार	96	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
76.	112272	सुभाष चंद्र	99	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
77.	145036	सुदीप शर्मा	102	पिछड़ा वर्ग को महिला
78.	151078	बनारस चंद्र	120	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
79.	169469	अनिल कुमार	121	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
80.	148700	संजय कुमार	131	पिछड़ा वर्ग को महिला
<b>(8) सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी:</b>				
81.	158658	संजय कुमार	55	सामान्य
82.	111878	अमित कुमार	57	सामान्य
83.	111982	संजय कुमार	58	सामान्य
84.	120748	सुदीप शर्मा	59	सामान्य
85.	117512	विशाल कुमार	81	सामान्य
86.	168788	अनिल कुमार	86	पिछड़ा वर्ग
87.	125496	विशाल कुमार दिवाकर	182	अनुसूचित जाति

2. उपर्युक्त 220 उम्मीदवारों में से अनुक्रमांक 111581, नीलम कृष्ण (मेधा क्रमांक-19) एवं अनुक्रमांक 111822, शशि शंकर (मेधा क्रमांक-40) द्वारा सेवाओं के लिए दिये गये आंशिक अधिमान-क्रम के अधीन उनके उक्त मेधा-क्रमांक तक तदनुसार रिक्ति शेष नहीं रही, जिस कारण उनकी नियुक्ति की अनुशंस नहीं की जा सकती है; उक्त दो उम्मीदवारों ने उक्त सभी आठ सेवाओं/पदों के लिए अपना अधिमान-क्रम अंकित नहीं किया है।

3. परीक्षाफल के मुद्दा की किसी जूटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

4. उपर्युक्त परीक्षाफल आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।

5. उपर्युक्त परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के लक्षात्क दिनक 30.01.2009 से आयोग के उक्त वेबसाइट पर प्रकाशित रहेंगे एवं तदनुसार ही इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

तिथि: 24 जनवरी, 2009

Certified  
Section Officer  
Bihar Public Service Commission  
PATNA

उप सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

अनुसूची - VII  
Annexure 04

# Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail id: infobasa1@gmail.com

**Shashank Shekhar Sinha**  
President

Mob. No.- 9334118192



**Anil Kumar**  
General Secretary

Mob. No.- 9431409463

Memo No 21

Date 13.07.2021

**ice President**  
d. Moezuddin  
9304951290

**Ajay Kumar**  
9835737317

**oint Secretary**  
ubodh Kumar  
7979919465

**opāl Sharan**  
8210342042

**Treasurer**  
il Kumar Tiwary  
9431085120

**int Treasurer**  
Mona Jha  
9430881025

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
सामान्य प्रशासन-विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

विषय:-

46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मुहैया कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

- (1) CWJC No-10901/2006 मो० कयुमुद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार वाद में दिनांक-03.08.2011 को पारित आदेश।
- (2) अधोहस्ताक्षरी का पत्रांक 09 दिनांक 15.01.2020 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं एवं वर्तमान में बिहार सरकार के अधीन दिनांक-01.09.2005 के बाद लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित है जबकि 47वीं बैच के पदाधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान अर्थात् पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिये जिसके निम्नलिखित आधार हैं;

2. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों हेतु चिन्हित रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन का प्रकाशन (छायाप्रति संलग्न) 05.11.2004 को किया गया था। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 14.12.2004 निर्धारित की गयी थी।

3. इस क्रम में दिनांक-14.12.2004 को हिन्दुस्तान दैनिक जागरण सहित अन्य समाचार पत्रों में विज्ञापन (छायाप्रति संलग्न) प्रकाशित किया गया, जिसमें उल्लिखित है कि 47वीं संयुक्त (प्रा०) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के क्रम संख्या-6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को परिभाषित करते हुए आवेदन जमा करने की तिथि को दिनांक-31.12.2004 तक बढ़ाया गया था।

h

4. उक्त विज्ञापन के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक-24.04.2005 को 47वीं संयुक्त (प्रो) प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी तथा इसका परीक्षा फल (छायाप्रति संलग्न) बि.लो.से. आयोग द्वारा 16.12.2008 को घोषित किया गया।
5. 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अन्तर्गत साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा 12.01.2009 से 14.01.2009 तक आयोजित की गयी एवं अंतिम परिणाम (छायाप्रति संलग्न) 24.01.2009 को घोषित किया गया।  
अतः उक्त साक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं;
- (क) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन वर्ष 2001 के आधार मानकर की गई है।  
(ख) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता हेतु प्रारम्भिक परीक्षा 24.04.2005 को आयोजित की गई है।  
(ग) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा हेतु चयनाचना मुख्य सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक 430 दिनांक 06.05.2005 के आलोक में की गयी है।
6. इस प्रकार स्पष्ट है कि 47वीं संयुक्त बिहार प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदों की रिक्तियाँ नई पेंशन योजना अर्थात् 01.09.2005 के पहले लागू नियमावली के आलोक में की गयी है। इसी प्रकार का समदृश्य मामला 46वीं बैच के पदाधिकारी का भी है।
7. इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC सं०-10901/2006 के कयामुद्दीन अंसारी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक 03.08.2011 को निम्नलिखित आदेश (छायाप्रति संलग्न) पारित है;

"It is infact this aspect of matter which would clinch the issue in favour of the petitioners in as much as it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules can not be made applicable."

8. उक्त न्याय निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किये गए पदाधिकारियों/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय।
9. अतः अनुरोध है कि उक्त न्यायादेश के आलोक में वित्त विभाग, बिहार सरकार में संकल्प सं० 1964 दिनांक 31.08.2005 की कंडिका 3 एवं कंडिका 6 में उल्लिखित प्रावधानों को स्थगित एवं क्षांत करते हुए 01.09.2005 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के लिए उच्चतरीय निर्णय लेने की कृपा की जाय।

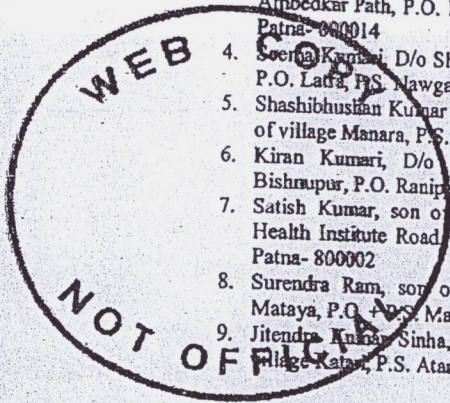
अनुलग्नक:-यथोपरि।

विश्वासभाजन  
(अनिल कुमार)  
महासचिव

विश्वासभाजन  
(शशांक शंखर मिहा)  
अध्यक्ष

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
CIVIL WRIT JURISDICTION CASE No.10901 of 2006

1. Md. Kayumuddin Ansari, son of Shri Rahmat Ali Ansari, resident of Latif Market, Chokhandi Road, P.S. Sasaram, Sasaram
2. Krishna Kumari, D/o Shri Ramji Prasad Gupta, resident of village Sikarhgarh Tola (L.C.T. Ghat Road), near Mishra Medical Hall, P.O. + P.S. Kahalgaon, District Bhagalpur
3. Arun Kumar, son of Shri Parasnath Prasad, resident of Khajpura Ambedkar Path, P.O. B.V.College, P.S. Shastrinagar, Bailey Road, Patna- 800014
4. Sneha Kumari, D/o Shri Ajeet Kumar Yadav, resident of village + P.O. Ladra, P.S. Nawgachhiya, District Bhagalpur
5. Shashibhushan Kumar Sinha, son of Shri Janardan Prasad, resident of village Manara, P.S. Noorsarai, District Nalanda
6. Kiran Kumari, D/o Shri Jagdish Prasad, resident of village Bishnupur, P.O. Ranipar, P.S. Noorsarai, District Nalanda
7. Satish Kumar, son of Shri Jaleshwar Prasad Singh, resident of Health Institute Road, Beur, P.S. Gardanibagh, Anisabad, District Patna- 800002
8. Surendra Ram, son of late Ramdeni Ram, resident of village Mataya, P.O. + P.S. Madhopur Ram, District Vaishali
9. Jitendra Kumar Sinha, son of Shri Rampriti Prasad, resident of village Katar, P.S. Atari, District Gaya



.....  
Petitioners

Versus

1. The State Of Bihar through the Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna
2. The Commissioner, Finance, Govt. of Bihar, Patna
3. The Commissioner cum Secretary, Health Services, Department of Health, Govt. of Bihar, Patna
4. The Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, Contributory Provident Fund, Bihar, Patna
5. The Additional Secretary, Health and Family Welfare, Department, Vikash Bhawan, Patna
6. The State Drugs Controller, Directorate Health Services, Vikash Bhawan, Patna
7. The Bihar Public Service Commission, Bihar, patna, through its Secretary

.....  
Respondents

For the petitioners : Mr. Mithilesh Kumar Rai, Adv.  
For the State : Mr. Bijay Kumar Pandey, A.C. to G.P.20  
For the BPSC : Mr. Sanjay Pandey, Adv.

5. 3.8.2011

Having heard counsel for the parties as with regard  
to the following relief:

"That this is an application for issuance of a writ in  
the nature of mandamus directing and commanding

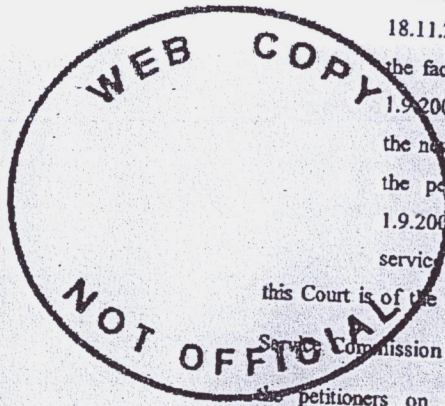


21

the respondent authorities not to give effect to letter no. 690 dated 3.3.2006, issued under the signature of the Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, so far as it relates to the petitioners, which is said to have been pursuant to Gazette notification bearing No. 614 dated 18.11.2005, whereby and whereunder it speaks of the fact that the persons having been appointed on 1.9.2005 or thereafter, shall have to be a member of the newly contributory fund scheme, as also to treat the petitioner to have been appointed prior to 1.9.2005 for the purposes of application of the service condition in regard to pension."

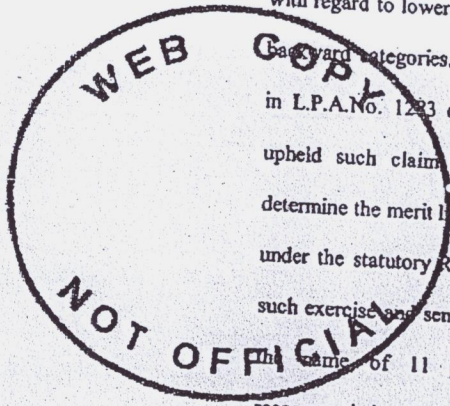
this Court is of the considered opinion that as the Bihar Public Service Commission had ultimately recommended the names of the petitioners on 25.6.2004 in continuation to the earlier recommendation of 41 candidates vide its letter No. 39 dated 12.5.2003 by making it clear that the name of the petitioners shall be placed below the 40<sup>th</sup> candidate and above 41<sup>st</sup> candidate, there should have been no difficulty for the Government to allow the benefit of old pension scheme which was prevalent at the time of appointment of the 41<sup>st</sup> candidate.

The issue in fact becomes very simple if it is taken into account that by one advertisement No. 2 of 2000 the post of Drug Inspector were advertised but when the result of the same was published in the year 2001 the petitioners were shown to have been unsuccessful in the written test, whereas the Commission had recommended the name of the other 41 persons in the year 2003 after conducting interview and preparing selection list. The



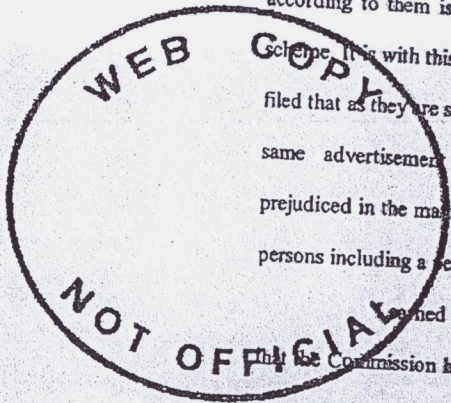
92

petitioners and the similarly situated persons like the petitioners thereafter had assailed the result and recommendation of the Commission on a ground that they were illegally edged out without following the Government's own scheme and policy as with regard to lowering qualifying mark in the written test for the backward categories. This Court in its judgment dated 16.5.2002 in L.P.A.No. 1283 of 1999 and its analogous cases in fact had upheld such claim and had directed the Commission to re-determine the merit list on the basis of qualifying marks prescribed under the statutory Rules. The Commission thereafter had made such exercise and sent its recommendation on 25.6.2004 wherein the name of 11 persons including the petitioners were recommended and it was clarified that their place of seniority will be below Sl.No. 40 and above Sl.No. 41 of the earlier list dated 12<sup>th</sup> May, 2003. Consequently such recommendation of the petitioners had not only been accepted by the Government but an offer of appointment was also issued to them on 11.8.2005 communicating that the Government had already decided them to appoint on the post of Drug Inspector and as such they should give their option of three districts for their respective place of posting. While all these things had already happened, the Government had taken a decision that from 1.9.2005 any person appointed in the Government service will not be entitled to the existing policy of pension being paid to them under the Bihar Pension Rules and they would be governed by a new contributory pension scheme framed by the government. Eventually when the petitioners were



23

also appointed by a notification dated 28.11.2005 they were also deprived of the benefit of pension under old policy and scheme governed by Bihar Pension Rules and they were also coerced to accept the new policy of Contributory Pension Scheme which according to them is less beneficial in comparison to the earlier scheme. It is with this grievance that this writ application has been filed that as they are senior to the persons appointed on the basis of same advertisement and selection process they cannot be prejudiced in the matter of service condition as was given to other persons including a person below them in the merit list.

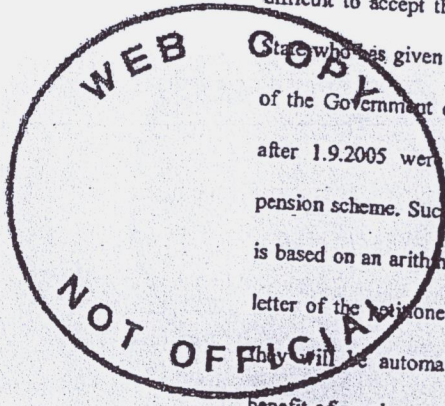


Learned counsel for the Commission has clarified that the Commission had gone into this exercise and had made its recommendation very clear that the place of the petitioners as per roster and reservation in view of the direction given by this Court in the judgment dated 16.5.2002 in L.P.A. No. 1823 of 1999, would be below S.No.40 of the original list and above 41 of the same list. In fact the Commission has itself placed the revised recommendation dated 25.6.2004 and Mr. Pandey, appearing on behalf of the Commission, has also very fairly produced even the earlier recommendation 12.5.2003, which has been kept on the records of this case. From the simultaneous reading of the two recommendations of the Commission dated 12<sup>th</sup> May, 2003 and 25.6.2003 it would become absolutely clear that the petitioners will be deemed to be appointee of the same transaction and barring the benefit of payment of salary for the period they had not worked on account of denial of their appointment they were entitled for all



other benefits including seniority to which were extended to other 41 Drug Inspectors appointed earlier - in view of the recommendation of Commission in its letter dated 12.5.2003.

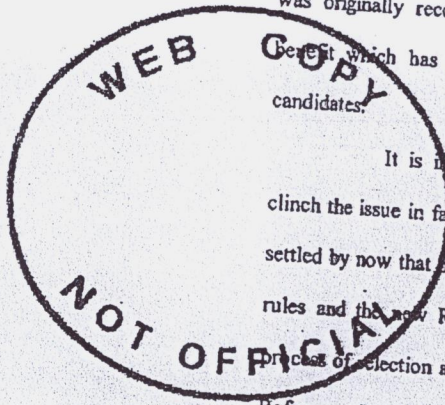
In that view of the matter, this Court would find it difficult to accept the submission of the learned counsel for the State who has given only one explanation by way of justification of the Government decision that the petitioners being appointee after 1.9.2005 were to be governed by the new contributory pension scheme. Such submission of learned counsel for the State is based on an arithmetical calculation that since the appointment letter of the petitioners was issued after cutoff date of 1.9.2005 they will be automatically deprived from availing the earlier benefit of pension under Bihar Pension Rules which was given to the appointees of the year 2003. This Court however would fail to understand the logic of such submission, inasmuch as when the petitioners were subjected to same selection process in terms of the same advertisement and ultimately their case was recommended by the Commission in continuation of the same merit list by placing them above a person who was originally recommended and appointed, it would be difficult to accept such justification given by the State Government that the petitioners still will be deprived of the benefit of the old pension scheme because they were appointed after 1.9.2005. It was not the fault of the petitioners that the Commission and/or the Government did not follow its own policy of following its decision regarding lower qualifying marks for the candidates belonging to backward



25

category and therefore, if the Government and the Commission had to be directed by this Court in the case filed by the similarly situated persons for drawing a fresh merit list, and in such merit list the name of the petitioners had figured above someone who was originally recommended, they cannot be deprived of the benefit which has been given to the originally recommended candidates.

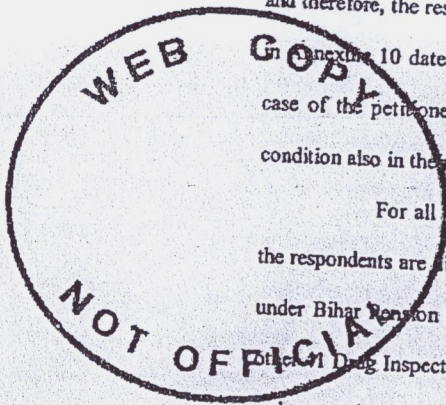
It is in fact this aspect of the matter which would clinch the issue in favour of the petitioners inasmuch as it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new Rules coming into force after beginning of process of selection as per old Rules cannot be made applicable. Reference in this connection may be usefully made to the judgment of Apex Court in the case of P. Mahendran Vs. State of Karnataka reported in (1990) 1 SCC 411. Moreover a right to receive pension is condition of service as has been held by the Apex Court in the case of Union of India Vs. Gurnam Singh reported in (1982) 2 SCC 314 and thus to be governed in accordance with the terms and condition of the advertisement and the existing Rules inasmuch he acquires a right to be considered for selection and appointment in accordance with the then existing Rules. This Court would accordingly hold that the petitioners being appointees of the old transaction of Advertisement No. 2 of 2000 in continuation with old appointees of 2003 will be entitled to get the benefit of old pension scheme and they will not be governed by the new Contributory Pension Fund Scheme coming



26

into force w.e.f. 1.9.2005. It has to be also kept in mind that even the original appointment letter issued on 26.11.2005 to the petitioners, did not contain any clause and/or condition that they will be governed by the new Contributory Pension Fund Scheme and therefore, the resolution of the Finance Department, contained in Annexure 10 dated 1.9.2005, cannot be made applicable in the case of the petitioners as it was not made part of their service condition also in their appointment letter.

For all these reasons, this application is allowed and the respondents are directed to give benefit of old pension scheme under Bihar Pension Rules to the petitioners as was extended to District Drug Inspectors appointed out of the same advertisement and transaction.



Surendra/

(Mihir Kumar Jha, J.)

अनुवृत्त - IX

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

CWJC No. 2312 /2022

Bihar Administrative Service Association through its General Secretary.

.....Petitioner

Versus

The State of Bihar and others .....Respondents

Subject:- Govt. Service-Others (Gazetted)

INDEX

<u>Sl No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page nos.</u>
	Synopsis	
1.	In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India	... 1-10
2.	Annexure-1 Series A copy of the aforesaid advertisements published in February 2004 and 05.11.2004	... 11-12
3.	Annexure-2 Series A copy of the final result of 46 <sup>th</sup> and 47 <sup>th</sup> batch officers so published on 27.06.2007 and 24.01.2009 by BPSC, Patna	13-15
4.	Annexure-3 A copy of the Letter No. 10059, dt. 10.11.2005 issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar (now GAD, Government of Bihar)	... 16-17
5.	Annexure-4 A copy of the aforesaid representation contained in Memo No. 21, dt.13.07.2021	.... 18-26
6.	Vakalatnama.	

1

28.12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

CWJC No. 2312 /2022

Bihar Administrative Service Association through its General Secretary.

.....Petitioner

Versus

The State of Bihar and others

.....Respondents

Synopsis

Relief Prayed for:-

For issuance of appropriate writ or writs in the nature of mandamus directing and commanding the respondent authorities to give benefit of old pension scheme under Bihar Pension Rules to the members of the petitioner association who had been appointed under 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> Batch of Bihar Administrative Service and further not to give effect to Clause 03 and Clause 06 of the Resolution No. 1964 dt. 31.08.2005 of the Finance Department, Govt. of Bihar and to lax the same with respect to them as they had been appointed under 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> Batch through advertisements published by the respondent Bihar Public Service Commission in February and November 2004 respectively, for the older vacancies of the year upto 2001-02, which was much before the cutoff date of 01.09.2005 for the new contributory pension scheme and thus, they are entitled to old pension scheme and not with the new contributory pension scheme; under which they have been brought arbitrarily and discriminately by the respondent authorities, and



For any other relief or reliefs as the Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

**Relevant date with brief facts:-**

**February 2004 and 5.11.2004** : Advertisement for appointment to the existing older vacancies of posts of Bihar Administrative Service, Bihar Finance Service, Bihar Education Service and Bihar Labour Service (General), Bihar Jail Service, Assistant Recruitment Officers etc. was published in the Hindi Daily Dainik Jagran , Hindustan and as well as English daily Times of India, Patna in February 2004 and 05.11.2004 respectively for 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> batch of Joint (Preliminary) Competitive Examination. Annexure-1 Series.

**11.10.2005**: At no point of time it was mentioned that they (selected appointees under 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> Batch) despite being appointed against old vacancies will be governed by the new contributory pension scheme made applicable with effect from 1-9-2005. Annexure-3

**27.06.2007 and 24.01.2009**: The Preliminary Competitive Examination of the 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> Batch for older vacancies were held prior to May 2005(24.04.2005) and final results were published on 27.06.2007 and 24.01.2009. Annexure-2 Series

**13.7.2021**: Petitioner association has submitted a representation with details of facts and also the order of Hon'ble High Court dt. 03.08.2011 passed in CWJC No. 10901 of 2006 before the General Administration Department, Government of Bihar vide its Memo No. 21 dt. 13.07.2021, however, no decision has been taken and no order has been passed and still the members of petitioner association belonging to 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> batch are being deprived of their legal entitlement. **Annexure-4**  
Hence the urgency of the present case.

4 of 12

Filed through:  
Abhay Shanker Singh 29/01/2022  
Abhay Shanker Singh, Adv.

AOR No. 01994

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

CWJC No. 2312/2022

In the matter of an application under Article  
226 of the Constitution of India

AND

In the matter of :-

Bihar Administrative Service Association through its General Secretary Sri  
Anil Kumar, son of Late Raja Ram Singh, aged about 56 years, Male, having  
its office at BASA BHAWAN, North of Income Tax Golamber, III. Nehru  
Marg, Patna ----- Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through the Chief Secretary, Government of Bihar,  
Patna
2. The Principal Secretary, Department of Finance, Government of Bihar,  
Patna
3. The Principal Secretary, General Administration Department,  
Government of Bihar, Patna
4. The Commissioner, Finance, Government of Bihar, Patna

5. The Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, Government of Bihar, Patna
6. The Bihar State Public Service Commission through its Secretary, Jawaharlal Nehru Road, Patna
7. The Accountant General, Bihar, Patna

--- --- Respondents

To

Hon'ble Mr. Justice Sanjay Karol, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justices at the said Court

Humble application on behalf of the aforesaid petitioner

**Most Respectfully Sheweth:**

1. That the petitioner Association beseeches indulgence of this Hon'ble Court for the following relief/s:
  - (a) For issuance of appropriate writ or writs in the nature of mandamus directing and commanding the respondent authorities to give benefit of old pension scheme under Bihar Pension Rules to the members of the petitioner association who had been appointed under 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> Batch of Bihar Administrative Service and further not to give effect to Clause 03 and Clause 06 of the Resolution No. 1964 dt. 31.08.2005 of the Finance Department, Govt. of Bihar and to lax the same with respect to them as they had been appointed under 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> Batch through advertisements published by the respondent Bihar Public Service Commission in February and November 2004 respectively, for the older vacancies of the year upto 2001-02, which was much before the cutoff

date of 01.09.2005 for the new contributory pension scheme and thus, they are entitled to old pension scheme and not with the new contributory pension scheme; under which they have been brought arbitrarily and discriminately by the respondent authorities.

(b) For any other relief or reliefs as the Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

2. That the issues of seminal importance raised in this writ petition are as follows:-

- i. Whether the members of petitioner association who were appointed in pursuance to advertisements published before 01.09.2005 under 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> batch for the older vacancies, are not entitled to old pension scheme and the Resolution of the government vide No. B64 dt. 31.08.2005 is not applicable to them?
- ii. Whether the members of petitioner association appointed in 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> batch of the BPSC are being covered under new pension scheme in most mechanical, arbitrary and unreasonable manner?
- iii. Whether non-inclusion of members of petitioner association appointed in 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> batch under the old pension scheme deprive them of their right as guaranteed under Article 14, 16, 21 and 300A of the Constitution of India?

3. That it is stated that the Petitioner is an Association of Bihar State Administrative Service Officers with Registration No. 663/2003 under Societies Registration Act, 1860 and this writ petition is being filed through its General Secretary in representative capacity because the issue raised herein affects all the members of the petitioner Association; so appointed through Advertisement for 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> Joint Competitive Examinations of BPSC and is of common interest.

4. That it is stated that the advertisement for appointment to the existing vacancies of posts of Bihar Administrative Service, Bihar Finance Service, Bihar Education Service and Bihar Labour Service (General), Bihar Jail Service, Assistant Recruitment Officers etc. was published in Hindi Daily Dainik Jagran, Hindustan and as well as English daily Times of India, Patna in February 2004 and 05.11.2004 respectively for 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> batch of Joint (Preliminary) Competitive Examination (those appointed through this are hereinafter referred as 46<sup>th</sup>-47<sup>th</sup> batch officers).

A copy of the aforesaid advertisements published in February 2004 and 05.11.2004 are annexed as Annexure-01 Series.

5. That it is stated that the Preliminary Competitive Examination of 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> Batch for older vacancies were held prior to May 2005 (24.05.05) and final results were published on 27.06.2007 and 24.01.2009 respectively.

A copy of the final result of 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> batch officers so published on 27.06.2007 and 24.01.2009 by BPSC, Patna is annexed as Annexure-2 Series.

6. That in respect of the 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> Joint Competitive Examination, following facts are pertinent to be considered:

- (i) The advertisements were published by the respondent Bihar Public Service Commission in February and November 2004 respectively for the older vacancies of the year upto 2001-02, which was much before the cutoff date of 01.09.2005 for the new contributory pension scheme.
- (ii) The Preliminary Tests were held prior to May 2005.

- (iii) The requisition for Bihar Administrative Service pursuant to 47<sup>th</sup> Joint Competitive Examination were sought by the BPSC vide Letter No. Letter No. 430, dt. 06.05.2005, again much before the cutoff date of 01.09.2005 for the new contributory pension scheme.
- (iv) The appointments against the older vacancies upto 2001-02 were covered under circular no. 502 dated 2-11-2002 of the Department of Personnel and Administrative Reforms; Government of Bihar (now GAD, Government of Bihar), as is evident from Letter No. 10059, dt. 10.11.2005 issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar (now GAD, Government of Bihar)
- (v) At no point of time it was mentioned that they (selected appointees under 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> Batch) despite being appointed against old vacancies will be governed by the new contributory pension scheme made applicable with effect from 1-9-2005.

A copy of the Letter No. 10059 dt. 10.11.2005 issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar (now GAD, Government of Bihar) is annexed as Annexure '03' to this writ petition.

7. That it is stated that in light of aforesaid, the older vacancies of the Bihar Administrative Service for the 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> Joint Competitive Examination were notified prior to the cutoff date of 01.09.2005 relevant for the new pension scheme and the process had begun under the old rules for the older vacancies and as such the old pension scheme shall be applicable for them.

8. That it is stated that under similar circumstances, some of the Drug Inspectors who were appointed after 1-9-2005 but pursuant to old advertisement and selection process had preferred a writ petition vide CWJC No. 10901 of 2006 claiming that they would not be covered by the resolution of government regarding applicability of new pension scheme to the effect that those appointed on 01.09.2005 and thereafter, shall have to be a member of newly contributory Pension fund scheme, and they claimed to be treated to have been appointed prior to dt. 01.09.2005 for pension purpose and the Hon'ble Court allowed the writ petition vide order dt. 03.08.2011 with observation that **it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules, cannot be made applicable.**
9. That it is stated that the petitioner association has submitted a representation with details of facts and also the order of Hon'ble High Court dt. 03.08.2011 passed in CWJC No. 10901 of 2006 before the General Administration Department, Government of Bihar vide its Memo No. 21 dt. 13.07.2021, however, no decision has been taken and no order has been passed and still the members of petitioner association belonging to 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> batch are being deprived of their legal entitlement.

A copy of the aforesaid representation contained in Memo No. 21, dt. 13.07.2021 is annexed hereto as Annexure '04' to this writ petition.

10. That it is submitted that as the advertisements were brought before the cutoff date 01.09.2005 and the process of selection was initiated under old pension scheme under Bihar Pension Rules, the members of petitioner association under 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> batch, are entitled to old pension scheme.

11. That it is submitted that the delay in the process of selection on account of litigation or otherwise cannot be attributed and made detrimental for the members of 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> batch selected BASA officers and it was only due to the procedural requirements and other exigencies on part of the respondents.
12. That the action/inaction on the part of the respondents is unjust, unfair and arbitrary and as such the same is violative of Article-14 of the Constitution of India.
13. That it is submitted that the deprivation of 46<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup> batch officers of petitioner Association from benefits of old pension scheme under Bihar Pension Rules is violative of Article 14, 16, 21 and 300A of the Constitution of India.
14. That it is stated that the petitioner has not preferred any other writ petition for the relief /s prayed herein.
15. That it is stated that the petitioner does not have alternative efficacious remedy than to prefer this writ petition.

It is, therefore, prayed that your lordships be graciously pleased to admit the application issue Rule NISI calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs prayed for above may not be granted and upon return of the rule and on such cause as may be shown and after hearing the counsel for the parties be pleased to make the same absolute.



And / or

Pass such order/orders as your lordships  
may deem fit and proper in the given facts  
and circumstances of this case.

And for this the Petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Anil kumar aged about 56 Years, (Male), son of Late ~~Dr. Raj~~ Ram Singh, resident of Village-Sareyan Basnat, P.O - Rampur Kesho Amnour P.S.- Taraiyan District -Saran, do hereby solemnly state and affirm as follows: -

1. That I am <sup>General</sup> Secretary of the Petitioner Association in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of this writ petition have been drafted under my instructions and I have read the contents thereof which I have fully understood.
3. That it is stated that the averments made under Para 3, 6P, 9P and 14 are true to the best of my knowledge and under Para 4, 5, 6P, 7P, 8 and 9P are true to best of my information and the rest are by way of submission before the Hon'ble Court.
4. That the annexure/annexures are true copy of the original's copy.

Anil Kumar

सहसचिव  
विहार प्रशासनिक सेवा संघ  
बिहार, पटना